

04 कार्यालय मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता)

1. यह संगठन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण पश्चात् दिनांक 21.12.2000 को अस्तित्व में आया है।
2. यह मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) का कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निर्माण वभागों यथा लोक निर्माण वभाग, जल संसाधन वभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी वभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा वभाग तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों का आंशिक निरीक्षण/निगरानी का है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन वभाग द्वारा निर्दिष्ट विशेष शिकायतों की जांच भी शामिल है।
3. वर्ष 2016-17 में व भन्न कार्य वभागों के चल रहे 203 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया एवं 143 निरीक्षण प्रतिवेदनों को समीक्षा उपरांत बंद किया गया। 31 मार्च 2017 तक व भन्न निर्माण वभागों से अपूर्ण जानकारी प्राप्त होने के कारण कुल 1371 प्रकरण लंबित है। प्रकरण निराकरण हेतु व भन्न निर्माण वभागों को निरंतर स्मरण कराया जा रहा है।
4. वर्ष 2017-18 में व भन्न वभागों को 205 कार्यों का निरीक्षण कये जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके वरुद्ध 30 दिसम्बर 2017 तक कुल 133 कार्यों का निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया गया है। वर्ष 2017-18 में 165 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों को समीक्षा उपरांत बंद किया गया है।
5. संगठन के द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये तकनीकी आपत्ति के वरुद्ध वभागीय अधिकारियों द्वारा संबंधित कार्यों के अनुबंधों से शास्ति के रूप में वर्ष 2016-17 में रु. 56.52 लाख राश वसूली करायी गई थी एवं वर्तमान वर्ष 2017-18 में 30 दिसम्बर 2017 तक रु. 48.97 लाख की वसूली शास्ति के रूप में की गई है।
6. 31 मार्च 2017 तक कुल लंबित जांच प्रकरणों की संख्या 05 है तथा वर्ष 2017-18 में 09 जांच प्रकरण प्राप्त हुये है। इस तरह कुल 14 जांच प्रकरणों के वरुद्ध 30 दिसम्बर 2017 तक 02 प्रकरण का निराकरण किया गया है, शेष 12 प्रकरणों में जांच प्रक्रियाधीन है।
7. संगठन के अंतर्गत कुल 27 पद स्वीकृत है जिसमें से 15 पद प्रतिनियुक्ति के है एवं 12 पद सीधी भर्ती से भरा जाना है। स्वीकृत संरचना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के 09 पद भरे है एवं 06 पद रिक्त है, इस प्रकार सीधी भर्ती के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक सहायक अभ्यंता सवल का पद भरा है तथा स्थापना के व भन्न 11 पद रिक्त है।

8. वर्ष 2017-18 में संगठन को रू. 172.52 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। जिसके वरुद्ध वर्तमान में 30 नवम्बर 2017 तक संगठन द्वारा नियमत स्थापना के वेतन एवं अन्य मदों पर कुल रू. 84.11 लाख व्यय किया गया है।